(b) Employment in the organised private sector (all non-agricultural establishments in the private sector with 10 or more workers), as on 31st March of 1985 (beginning of the seventh Plan), 1990 (end of the Seventh Plan), 1992 (beginning of the Eighth Plan) and 1996 was as indicated below:—

As on 31st March	Employment (lakh)
1985	73.09
1990	75.82
1992	78.50
1996	84.68

Slippage in India's Export Growth rate

981. SHRI RAMDAS AGARWAL: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the editorial captioned "India's Foreign trade losses bounce" in the Financial Express, New Delhi, dated 4th November, 1996;

(b) whether the country's export growth has slowed down to 9.9 per cent in April-September this year from close to 27 per cent in the first half by last year;

(c) whether it is a fact that a report on global competitivenss of 49 countries shows that India slipped from the 35th position in 1994 to the 45th position currently;

(d) if so, the main reasons therefor; and

(e) steps Government have taken so far to achieve their trade growth targets for 1996-97?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI BOLLA BULLI RAMAIAH): (a) Yes, Sir.

(b) As per DGCI&S data, growth in exports in dollar terms during April-September of the current financial year has been 9.91% over the corresponding period in 1995-96 compared to overall annual growth of 18.4% in 1994-95 & 21.0% in 1995-96.

(c) and (d) Sir, a study by the World Economic Forum a private organisation, based in Switzerland appears to have indicated a decline in India's ranking in world competitiveness. However, as per WTO data, India's ranking in world exports has slightly improved in 1995.

(e) Export Promotion is a continuous process and steps are initiated by the Government to promote exports through simplification of policies and procedures, improving bilateral trade, debottlenecking of export infrastructure and giving special thrust to value added exports.

देश में खनिजों का उत्पादन

982. **श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल:** क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में खनिजों का राज्य-वार और वर्ष-वार कितना-कितना उत्पादन हुआ;

(ख) क्या यह उत्पादन देश की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा खनिजों का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

खान मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव): (क) वर्ष 1993-94 से 1995-96 के दौरान राज्यवार खनिज उत्पादन अनुबंध में दिया गया है। (देखिए परिशिष्ट 179, अनुपत्र संख्या 19)

(ख) से (ग) भारत फिलहाल खनिज आधारित उद्योगों के लिए बहुत से खनिजों में आमतौर पर आत्मनिर्भर है। देश कुल मिलाकर धात्विक खनिजों में कोयले (बेहदनिम्न किस्म को कोकिंग कोल के सिवाय) लिग्नाइट, बाक्साइट, क्रोमाइट, लौह तथा मैंगनीज अयस्क, इल्मेनाइट, स्टाइल तथा क्राइसोटाइल एवं एस्बेस्टोस, बोरेइस, पोटाश, रॉक फास्फेट और एलीमेंटल सल्फर को छोड़कर लगभग सभी औद्योगिक खनिजों में आत्मनिर्भर है। आत्मनिर्भरता के बावजूद विशेष ग्रेड के फ्लोर्सपर, फ्लेकी और हाई फिकस्ड कार्बन वाले एमोरफोस ग्रेफाइट, निम्न सिलिका, चूनापत्थर, मृत-जला मैग्नेशिया तथा समुद्री जल मैग्नेशिया इत्यादि आयात किये जाते हैं। भारत अपने मूल्य वर्धित पुनर्निर्यात के लिए कच्चे बिनाकटे हीरे, माणिक्य तथा अन्य बहुमूल्य तथा अर्द्ध-कीमती पत्थरों के आयात पर भी निर्भर कर रहा है।

(घ) नई राष्ट्रीय खनिज नीति, 1993 में अन्य बातों के साथ-साथ, गवेषण और खनन के क्षेत्र में घरेलू तथा विदेशी दोनों निजी क्षेत्रों द्वारा निवेश का प्रावधान है। 1994 में खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम 1957 में किए गए संशोधन से उसे निजी निवेशों में आसानी होगी। इससे देश में खनिजों के उत्पादन में बढ़ोतरी होगी।